विचार बिन्दु

बच्चों को पालना, उन्हें अच्छे व्यवहार की शिक्षा देना भी सेवाकार्य है, क्योंकि यह उनका जीवन सुखी बनाता है। –स्वामी रामसुखदास

शिक्षा का बदलता स्वरूपः राजस्थान में चुनौतियां और संरक्षण के सरकारी उपाय

शिक्षा मानव सभ्यता का मूल आधार है। यह व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और मूल्यों से सुसज्जित कर समाज को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। आजादी के बाद से भारत में शिक्षा का स्वरूप निरंतर विकसित हो रहा है, लेकिन डिजिटल युग ने इसे अभूतपूर्व गति प्रदान की है। कोविड–19 महामारी ने पारंपरिक कक्षा–कक्ष शिक्षा को ऑनलाइन मोड में धकेल दिया, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एआई आधारित लर्निंग ऐप्स और वर्चुअल क्लासरूम मुख्यधारा बन गए। राजस्थान जैसे विविधतापूर्ण राज्य में यह परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप तेजी से घटित हो रहा है। राज्य सरकार ने डिजिटल डिवाइड, गुणवत्ता ह्रास और सांस्कृतिक क्षय जैसी चुनौतियों से निपटने हेतु बहुआयामी संरक्षण उपाय अपनाए हैं।

शिक्षा का परंपरागत स्वरूप गुरुकुल परंपरा पर आधारित था, जहाँ गुरु–शिष्य संबंध के माध्यम से समग्र विकास होता था। औद्योगिक क्रांति और वैश्वीकरण ने इसे औपचारिक स्कूलों तक सीमित कर दिया। अब 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी ने इसे क्रांतिकारी रूप प्रदान किया है। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और हाई–स्पीड इंटरनेट ने शिक्षा को सीमाहीन बना दिया। एनईपी 2020 ने इसे पुष्ट किया, जिसमें 5 3 3 4 की नई संरचना अपनाई गई–फाउंडेशन (3–8 वर्ष), प्रिपरेटरी (8–11), मिडिल (11–14) तथा सेकेंडरी (14–18)। बहुभाषिकता, कौशल विकास और भारतीय ज्ञान प्रणाली पर जोर दिया गया। डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं, एनपीटीईएल, ई–पाठशाला जैसे पोर्टल्स लाखों छात्रों को जोड़ रहे हैं। एआई आधारित प्लेटफॉर्म्स जैसे बायजूज, अनएकेडमी छात्र की गति अनुसार पाठ्यक्रम ढालते हैं। वर्चुअल रियलिटी (वीआर) से छात्र ताजमहल के अंदर भ्रमण कर वास्तुकला सीख सकते हैं। उदाहरणस्वरूप, 2025 में राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में वीआर के माध्यम से उदयपुर के झील महल का डिजिटल दौरा कराया गया, जिससे छात्रों की रुचि दोगुनी हो गई। ये नवाचार शिक्षा को रोचक और सुलभ बना रहे हैं।

राजस्थान में यह परिवर्तन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढल रहा है। राज्य में 1.07 लाख से अधिक स्कूल हैं, जहां 7.75 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। 2023–24 से विश्वविद्यालय स्तर पर एनईपी लागू हो चुकी है। स्कूली स्तर पर चरणबद्ध क्रियान्वयन जारी है–2025–26 से कक्षा 1–5 में नया सिलेबस शुरू हुआ, जिसमें उदयपुर द्वारा तैयार भारतीय संस्कृति, इतिहास और व्यावहारिक ज्ञान शामिल है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जुलाई 2025 से प्राथमिक स्तर पर बड़े बदलाव की घोषणा की। एनसीईआरटी, एनसीएफ 2023 और राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुरूप वीर योद्धाओं, राजस्थान भूगोल, लोक संस्कृति को पाठ्यक्रम में स्थान मिला। डिजिटल इंडिया के तहत भारत नेट परियोजना ने ग्रामीण पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा है। पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसए) ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को साक्षर बनाया, जिसमें राजस्थान का बड़ा हिस्सा शामिल है। 2026 तक राज्य में 90 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हाई–स्पीड इंटरनेट पहुंच गया, जिससे 50 लाख छात्र लाभान्वित हुए।

शिक्षा का बदलता स्वरूप अवसर है, लेकिन असंतुलित हो तो विनाशकारी भी साबित हो सकता है। राजस्थान सरकार के उपाय एनईपी चरणबद्ध क्रियान्वयन, सिलेबस संशोधन, सांस्कृतिक एकीकरण प्रेरक हैं। समग्र शिक्षा, डिजिटल पहलें मील का पत्थर साबित हो रही हैं। समाज, शिक्षक, अभिभावक, नीति-निर्माता मिलकर प्रयास करें। राजस्थानी धरोहर सहेजें, आधुनिकता अपनाएँ। युवा सशक्त हों, राज्य प्रगति करे। विश्व गुरु भारत का स्वप्न साकार हो।

हालांकि, बदलते स्वरूप ने गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। प्रथम, डिजिटल डिवाइड। राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों–जैसलमेर, बाड़मेर में इंटरनेट पहुंच अभी भी सीमित है। यूनेस्को के अनुसार, भारत के 25 करोड़ छात्रों में 30 प्रतिशत डिजिटल वंचित हैं; राजस्थान में यह आंकड़ा 35 प्रतिशत से अधिक है। शहरी छात्र हाई–स्पीड नेट और डिवाइस से लैस हैं, जबकि ग्रामीण बच्चे किताबों तक सीमित रह जाते हैं। द्वितीय, गुणवत्ता ह्रास। ऑनलाइन शिक्षा में एकाग्रता की कमी से लर्निंग आउटकम घटे हैं। लंबे स्क्रीन टाइम से नेत्र समस्या, तनाव बढ़ा। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2021 के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान के ग्रामीण छात्रों का गणितीय प्रदर्शन 15 प्रतिशत गिरा। तृतीय, सांस्कृतिक क्षय। पश्चिमी एडटेक ऐप्स से राजस्थानी लोकगीत, कठपुतली, भोपाओं की परंपरा प्रभावित हो रही है। गुरु–शिष्य संबंध कमजोर पड़ गया। चतुर्थ, निजीकरण। कोचिंग संस्थान और एडटेक कंपनियाँ बाजारीकरण कर रही हैं, जिससे गरीब वंचित रह रहे हैं। उदाहरणस्वरूप, जयपुर के कोटा जैसे शहरों में एडटेक फीस 20 प्रतिशत बढ़ी, जबकि ग्रामीण आय समान रही।

राजस्थान सरकार ने शिक्षा संरक्षण हेतु सक्रिय कदम उठाए हैं। समठा शिक्षा अभियान (2021–26) के तहत 2.15 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें राज्य को पर्याप्त हिस्सा मिला। स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड स्थापित हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संभागीय कमेटियाँ गठित कीं, जो 186 स्कूलों का अपग्रेड सुनिश्चित कर रही हैं। 2026 तक 500 और स्कूल स्मार्ट बनेंगे। राजस्थानी भाषा प्रोत्साहन योजना से क्षेत्रीय भाषा, लोककथाएँ, लोकगीत पाठ्यक्रम में शामिल हैं। कला एवं हस्तशिल्प शिक्षा योजना स्कूलों में लोककलाएँ–कठपुतली, मांडणा, भोपा नृत्य सिखा रही है। एनईपी में भारतीय ज्ञान प्रणाली वेद, उपनिषद, योग, आयुर्वेद को स्थान दिया गया। डीआईईटी और डिजिटल आईसीटी शिक्षक प्रशिक्षण दे रहे हैं। नवोदय विद्यालयों का विस्तार मेधावी ग्रामीण छात्रों हेतु हो रहा है। पोर्टल से 25 प्रतिशत आरक्षण, छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जा रही हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को गति मिली। मिड–डे मील नामांकन बढ़ा रहा है। कोविड में डीआईएसएचए ने टीवी, रेडियो से 20 करोड़ छात्रों तक पहुँचा। एनएएस कमजोर क्षेत्र चिह्नित कर रहा है। जयपुर में पाठ्यक्रम समीक्षा समिति विश्वविद्यालय शिक्षाविदों संग कार्यरत है। बीकानेर के 15 स्कूल अपग्रेड हो चुके हैं। ये उपाय भाषाई विविधता मारवाड़ी, मेवाड़ी को सम्मान देते हैं।

सांस्कृतिक संरक्षण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजस्थान सरकार ने स्थानीय परंपराओं को एनईपी से जोड़ा। स्कूलों में भजन संध्या, कवि सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। हस्तशिल्प से छात्र स्वरोजगार सीख रहे हैं। महिला साक्षरता हेतु विशेष अभियान चल रहे हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु समावेशी शिक्षा लागू है। डिजिटल सुरक्षा हेतु साइबर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। समग्र शिक्षा से प्री–प्राइमरी तक एकीकरण हुआ। उदाहरणस्वरूप, जोधपुर के एक स्कूल में भोपा कलाकारों ने छात्रों को लोककथाएँ सिखाईं, जिससे सांस्कृतिक जुड़ाव 40 प्रतिशत बढ़ा। फिर भी कमियाँ बरकरार हैं। शिक्षा बजट जीडीपी का 6 प्रतिशत होना चाहिए, वर्तमान लगभग 4 प्रतिशत है। भ्रष्टाचार, क्रियान्वयन देरी बाधा बने हुए हैं। नामांकन ह्रास चिंताजनक है 2025 में प्राथमिक स्तर पर 5 प्रतिशत गिरावट दर्ज। रेगिस्तानी क्षेत्रों में इंटरनेट समस्या बनी हुई। निजीकरण नियंत्रण अपर्याप्त है। भविष्य हेतु एआई का नैतिक उपयोग आवश्यक सांस्कृतिक सामग्री युक्त ऐप्स विकसित करें। सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल अपनाएँ। शिक्षक भर्ती तेज करें। 2026 के राज्य बजट में 10,000 नई भर्तियाँ प्रस्तावित हैं।

शिक्षा का बदलता स्वरूप अवसर है, लेकिन असंतुलित हो तो विनाशकारी भी साबित हो सकता है। राजस्थान सरकार के उपाय एनईपी चरणबद्ध क्रियान्वयन, सिलेबस संशोधन, सांस्कृतिक एकीकरण प्रेरक हैं। समग्र शिक्षा, डिजिटल पहलें मील का पत्थर साबित हो रही हैं। समाज, शिक्षक, अभिभावक, नीति–निर्माता मिलकर प्रयास करें। राजस्थानी धरोहर सहेजें, आधुनिकता अपनाएँ। युवा सशक्त हों, राज्य प्रगति करे। विश्व गुरु भारत का स्वप्न साकार हो। सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े आधुनिक नागरिक गढ़ें। संरक्षण ही प्रगति का आधार है।

**–अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार**

दो वर्ष बनाम पांच वर्ष : राजस्थान में सुशासन, गति और विश्वास का नया अध्याय

यदि दावे के स्तर पर नहीं, बल्कि आंकड़ों की कसौटी पर परखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में शासन की शैली और प्राथमिकताओं में बड़ा बदलाव आया है

मदन राठौड़

राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक इतिहास में यह पहला अवसर है, जब कोई सरकार अपने कार्यकाल के मात्र दो वर्षों में न केवल अपने कामकाज का आंकड़ों सहित रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करे, बल्कि उसे पूर्ववर्ती सरकार के पूरे पाँच वर्षों से तुलनात्मक रूप से बेहतर सिद्ध करने का दावा भी आत्मविश्वास के साथ रखे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान प्रस्तुत किया गया दो वर्षों की उपलब्धियों का दस्तावेज़ इसी आत्मविश्वास का प्रतिफल है।

यह दस्तावेज़ केवल राजनीतिक वक्तव्य नहीं, बल्कि प्रशासनिक दक्षता, वित्तीय अनुशासन और विकास की स्पष्ट दिशा का संकेत देता है। मुख्यमंत्री का यह कथन कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पाँच वर्षों से अधिक कार्य हमारी सरकार ने दो वर्षों में किए हैं, यदि दावे के स्तर पर नहीं, बल्कि आंकड़ों की कसौटी पर परखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में शासन की शैली और प्राथमिकताओं में बड़ा बदलाव आया है।

पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय कुप्रबंधन का गहरा प्रभाव पड़ा। 5 लाख 79 हजार 781 करोड़ रुपये का कर्ज, खाली खजाना और अधूरी योजनाओ की विरासत नई सरकार को मिली। इसके विपरीत, वर्तमान सरकार ने केवल दो वर्षों में राजस्व घाटे को करीब 8 हजार करोड़ रुपये तक कम कर दिया। वर्ष 2023–24 में 38 हजार 954 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे को 2025–26 के बजट अनुमानों में 31 हजार 9 करोड़ रुपये तक लाना वित्तीय अनुशासन का स्पष्ट संकेत है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 में राजस्थान के आर्थिक प्रबंधन, सामाजिक क्षेत्र में नवाचार और प्रशासनिक सुधारों की विशेष सराहना इस बात की पुष्टि करती है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को केवल स्थिरता ही नहीं, बल्कि गति और दिशा भी मिली है।

केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और राज्य में भजनलाल शर्मा की सरकार के कारण डबल इंजन की अवधारणा धरातल पर साकार होती दिखी है। जहां पूर्ववर्ती सरकार को चार वर्षों में 15,803 करोड़ रुपये की पूंजीगत निवेश सहायता मिली, वहीं वर्तमान सरकार मात्र दो वर्षों में 19 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता केंद्र से प्राप्त कर चुकी है। वर्ष 2024–25 में 30 हजार 700 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय अब तक का सर्वाधिक है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में इस वर्ष राजस्थान को 90 हजार 445 करोड़ रुपये प्राप्त होना भी इस सहयोग का प्रतिफल है।

रामजल सेतु परियोजना के अंतर्गत नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध में जल संग्रहण प्रारंभ होना, 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों का धरातल पर उतरना और यमुना जल समझौते की डीपीआर का अंतिम चरण राजस्थान के जल भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में निर्णायक कदम हैं।

जहां पिछली सरकार ने पाँच वर्षों में 52,182 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा दी, वहीं वर्तमान सरकार ने दो वर्षों में ही 99,562 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई। यह अंतर केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि नीति और क्रियान्वयन की गति का भी है। कृषि क्षेत्र में किसान सम्मान निधि को दो वर्षों में डेढ़ गुना करना और 10,508 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित करना सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। 48,325 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त फसली ऋण, 73 लाख से अधिक फसल बीमा पॉलिसियां और 6,415 करोड़ रुपये का क्लेम वितरण जैसे कदम किसानों के आर्थिक संबल को मजबूत करते हैं।

22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली, 2 लाख से अधिक नए कृषि कनेक्शन और 48,591 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी मिलकर ठामीण अर्थव्यवस्था को ऊर्जा प्रदान करता है।

युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश पेपरलीक जैसे मामलों पर सरकार की सख्ती है। 140 एफआईआर और 428 से अधिक अपराधियों को जेल भेजना केवल कार्रवाई नहीं, बल्कि भरोसे की बहाली है। अब तक 1 लाख से अधिक नियुक्तियां, 1 लाख 55 हजार से अधिक भर्तियां प्रक्रियाधीन और निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार अवसर यह दर्शाता है कि सरकार रोजगार को घोषणाओं से निकालकर धरातल पर ला रही है।

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार अपराधों में 14.13 प्रतिशत की कमी, एससी–एसटी अत्याचारों में 28 प्रतिशत और महिला अपराधों में 10 प्रतिशत की गिरावट, ये आंकड़े कानून–व्यवस्था में सुधार की पुष्टि करते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक भुगतान, एनएफएसए में 73 लाख से अधिक नए लाभार्थी, 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर से 1 करोड़ परिवारों को राहत जैसे सभी कदम सामाजिक न्याय के विस्तार को दर्शाते हैं।

स्वास्थ्य, ऊर्जा और औद्योगिक भविष्य

'मा योजना' के तहत 7,645 करोड़ रुपये का कैशलेस उपचार, 34 नई औद्योगिक नीतियां और 'राइजिंग राजस्थान' के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू से स्पष्ट संकेत हैं कि प्रदेश औद्योगिक युग के नए चरण में प्रवेश कर चुका है।

सौर ऊर्जा में मात्र 25 महीनों में 19,209 मेगावाट की बढ़ोतरी, जबकि पिछली सरकार के पाँच वर्षों में यह आंकड़ा 14,878 मेगावाट था। यह अंतर नीति और निर्णय क्षमता को स्पष्ट करता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने दो वर्षों में जिस गति, पारदर्शिता और परिणामोन्मुखी शासन का अनुभव किया है, वह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि कार्य संस्कृति में बदलाव का संकेत है। सड़क, बिजली, पानी, कृषि, महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार और कानून–व्यवस्था हर क्षेत्र में आंकड़े बताते हैं कि दो वर्ष बनाम पाँच वर्ष की यह तुलना केवल राजनीतिक दावा नहीं, बल्कि प्रशासनिक उपलब्धि का ठोस प्रमाण है। आगामी तीन वर्षों में विकास की गति को और तेज करने का सरकार का संकल्प यदि इसी तरह आंकड़ों और परिणामों में बदलता रहा, तो राजस्थान का नाम देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित होना केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि स्वाभाविक परिणति होगी।

**–मदन राठौड़,
सदस्य, राज्यसभा**

–पुस्तक समीक्षा–

''सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि''

लेखक : वासुदेव देवनानी, विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान

'सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि' केवल एक राजनेता की जीवनी या विचार–संग्रह नहीं है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रबोध को समझने का एक वैचारिक प्रयास है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस पुस्तक के माध्यम से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, चिंतन और कार्यों को सनातन संस्कृति की दृष्टि से देखने का सार्थक प्रयास किया है। यह कृति अटल जी के व्यक्तित्व को राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठाकर एक सांस्कृतिक और नैतिक प्रतिमान के रूप में स्थापित करती है।

पुस्तक का केंद्रीय भाव यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक कुशल राजनीतिज्ञ या प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि वे भारतीय सनातन संस्कृति के जीवंत प्रतिनिधि थे। लेखक मानते हैं कि अटल जी की सोच, भाषा, व्यवहार और निर्णयों में भारतीय सभ्यता के शाश्वत मूल्य सहिष्णुता, समन्वय, मानवता, करुणा और राष्ट्रप्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पुस्तक में यह स्थापित किया गया है कि अटलजी का राष्ट्रवाद आक्रामक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास से उपजा हुआ था।

वासुदेव देवनानी अपनी इस पुस्तक में सनातन संस्कृति की परिभाषा को संकीर्ण धार्मिक दायरे से बाहर निकालकर एक व्यापक जीवन–

वासुदेव देवनानी, विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान।

दर्शन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार सनातन का अर्थ है जो शाश्वत है, जो समय के साथ बदलता नहीं, बल्कि समय को दिशा देता है। अटल बिहारी वाजपेयी इसी सनातन चेतना के वाहक थे। चाहे संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में दिया गया उनका ऐतिहासिक भाषण हो या विपक्ष में रहते हुए भी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन–हर प्रसंग में लेखक सनातन मूल्यों की झलक दिखाते हैं।

पुस्तक की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अटल जी के प्रमुख राजनीतिक निर्णयों को सांस्कृतिक दृष्टि से समझने का प्रयास किया गया है। पोखरण परमाणु परीक्षण को केवल सामरिक निर्णय न मानकर लेखक उसे राष्ट्र की आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जोड़ते हैं। इसी प्रकार, सड़क, संचार और आधारभूत ढांचे से जुड़ी योजनाओं को 'राष्ट्र निर्माण के यज्ञ' के रूप में देखा गया है। लेखक यह तर्क देते हैं कि अटल जी का विकास मॉडल केवल भौतिक उन्नति तक सीमित नहीं था, बल्कि वह सांस्कृतिक और मानवीय विकास को भी समान महत्व देता था।

शैली की दृष्टि से पुस्तक सरल, प्रवाहपूर्ण और प्रभावशाली है। भाषा न तो अत्यधिक दार्शनिक है और न ही शुष्क राजनीतिक। यही कारण है कि यह पुस्तक सामान्य पाठकों, विद्यार्थियों और युवा पीढ़ी के लिए भी सहज रूप से पठनीय बन जाती है। लेखक का अनुभव और वैचारिक स्पष्टता हर अध्याय में महसूस होती है। कई स्थानों पर अटल जी के विचार, कथन और घटनाएं पाठक को भावनात्मक रूप से भी जोड़ती हैं।

पुस्तक का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि इसमें अटल बिहारी वाजपेयी को एक आदर्श लोकतांत्रिक नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक बताते हैं कि सत्ता में रहते हुए भी अटल जी ने कभी अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। विरोधियों के प्रति सम्मान, संवाद की संस्कृति और संसदीय मर्यादाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आज के राजनीतिक परिदृश्य में और अधिक प्रासंगिक प्रतीत होती है।

पुस्तक अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रश्न भी उठाती है कि क्या आज की राजनीति अटल जी के मूल्यों से कुछ सीख लेने को तैयार है? हालाँकि, पुस्तक का वैचारिक झुकाव स्पष्ट है और यह अटल जी के व्यक्तित्व का अत्यंत सकारात्मक चित्र प्रस्तुत करती है। आलोचनात्मक विश्लेषण की अपेक्षा करने वाले पाठकों को यह पक्ष थोड़ा सीमित लग सकता है। फिर भी, पुस्तक का उद्देश्य आलोचना नहीं, बल्कि प्रेरणा देना है–और इस कसौटी पर यह पूरी तरह सफल होती है।

निष्कर्ष रूप में 'सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि' एक प्रेरक, विचारोत्तेजक और समयानुकूल कृति है। यह पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी को समझने के साथ–साथ भारतीय संस्कृति और राष्ट्रचिंतन को भी गहराई से समझने का अवसर देती है। जो पाठक अटल जी के विचारों, सनातन संस्कृति के मूल्यों और भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को जानना चाहते हैं, उनके लिए यह पुस्तक अवश्य पठनीय है। यह केवल अटल जी को स्मरण करने की पुस्तक नहीं, बल्कि उनके विचारों को आत्मसात करने का आमंत्रण है।

(पुस्तक समीक्षक–गोपेन्द्र नाथ भट्ट स्वतन्त्र लेखक और सलाहकार विधानसभाध्यक्ष, राजस्थान है।)

जिला कलैक्टर ने ग्राम उत्थान शिविर का किया निरीक्षण

कलैक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रामीणों को केंद्र व राज्य सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी प्रदान कर लाभांवित कराया जाए

अलवर, (निसं)। जिला कलैक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने उपखण्ड क्षेत्र राजगढ़ के गिरदारवर सर्किल ढिगावडा में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर का निरीक्षण कर विभिन्न विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किसानों को वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की।

जिला कलैक्टर ने शिविर में कृषि, पशुपालन, कॉपरेटिव, राजस्व, ऊर्जा, चिकित्सा विभाग सहित 12 विभागों की लगाई गई स्टालों का निरीक्षण कर शिविरि प्रभारी को निर्देश दिये कि आमजन के मूलभूत कार्यों को शिविर में ही सम्पादित करायें। उन्होंने निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी आवेदक को अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रामीणों को केंद्र व राज्य सरकार की तारबंदी, डिग्गी, पाइपलाइन, फार्म पॉण्ड, फव्वारा एवं ड्रिप, प्लास्टिक मल्च, सौर पंप संयंत्र की स्वीकृतियां, बैलों से खेती करने पर 30 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि, फसल बीमा एवं एमएसपी की जानकारी, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन, सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण, सोलर पंप एवं पॉलीहाउस के आवेदन तैयार करने सहित बीज एवं मिनी किट वितरण का सत्यापन, पीएमएफएमई के आवेदन तैयार करना, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के आवेदनों का निस्तारण, मुख्यमंत्री किसान निधि का डीबीटी, किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन, नवीन गोदाम निर्माण, डीसीएस द्वारा सहकारी बैंक में खाते, स्वयं सहायता समूहों के ऋण, 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना, सहकारिता सदस्यता आवेदन अभियान, सहकारी ऋण योजना की जानकारी एवं कस्टम हायरिंग सेंटर, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना अंतर्गत पंजीकरण, पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा एवं कृमिनाशक औषधि पिलाना, क्लासिकल स्वाइन फीवर रोग प्रतिरोधक टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, फर्टिलिटी किट का वितरण, पशु आहार एवं खनिज मिश्रण वितरण तथा गौशाला विकास योजनाओं की जानकारी प्रदान कर लाभांवित कराया जाए। उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि ग्राम उत्थान शिविरों में पहुंचकर योजनाओं का लाभ लें।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शनिवार 7 फरवरी, 2026

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठि तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, चित्रा नक्षत्र रात्रि 2:28 तक, शूल योग रात्रि 11:40 तक, गर करण दिन 2:07 तक, चन्द्रमा आज दिन 1:32 से तुला राशि में संचार करेगा।

गृह स्थितिः सूर्य–मकर, चन्द्रमा–कन्या, मंगल–मकर, बुध–कुम्भ, गुरू–मिथुन, शुक्र–कुम्भ, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह

आज सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 2:28 से सूर्योदय तक है। रवियोग रात्रि 2:28 से आरम्भ होगा। महापात योग रात्रि 9:37 से रात्रि 2:22 तक है। भद्रा रात्रि 2:55 से आरम्भ होगी।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 8:35 से 9:57 तक, चर 12:41 से 2:03 तक, लाभ–अमृत 2:03 से 4:47 तक।

राहूकालः 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 7:13, सूर्यास्त 6:09

मेष
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। दिन के मध्यान्ह पश्चात परिवार में धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

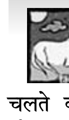

वृष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

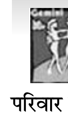

मिथुन
घर–परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

कर्क
परिवार शुभ–मांगलिक संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यक्तिगत प्रयासों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

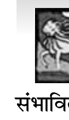

सिंह
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

तुला
व्यावसायिक यात्रा संभव है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

वृश्चिक
आर्थिक/वित्तीय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

धनु
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

मीन
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।